पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 559 करोड़ रुपये की गिरावट आयी है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा लागू की गयी नयी आर्थिक नीति के लाभ उद्योग को मिल रहे हैं।

**औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना में विलम्ब**

564 श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1988 में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश भर में औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने का निश्चय किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अभी तक देश में इस प्रकार के मात्र 37 केन्द्र स्थापित किये जा सके हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी कम संख्या में इन केन्द्रों की स्थापना होने के क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार ने गत वर्षों में इस योजना के परिणामों की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस योजना से देश में रोजगार के अवसरों और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में उसकी भावी योजना क्या है?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत 70 विकास केन्द्रों का विकास करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा किसी केन्द्र की परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के पश्चात चुनिंदा केन्द्रों संबंधी कार्य किया जाता है। अभी तक 64.74 करोड़ रु0 की केन्द्रीय सहायता से 39 परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदित केन्द्र कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ङ) से (छ) चूंकि योजना अभी कार्यान्यवनाधीन है इसलिए इसके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए छह वर्षीय योजना**

565 श्री वीरेन जे० शाह :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों के पुनरुद्धार हेतु एक छः वर्षीय योजना तैयार करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रस्तावित रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन संस्थानों को हो रही आर्थिक हानि के क्रम में आगामी छः वर्षों तक कोई कमी आने की सम्भावना नहीं है;

(घ) यदि नहीं, तो इन संस्थानों को लाभप्रद बनाने हेतु वार्षिक रूप से खर्चे में कितनी कमी किये जाने का विचार है; और

(ङ) इन संस्थानों को आगामी छः वर्षों में कितनी हानि होने का अनुमान है?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा उद्यमों के प्रबंध द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार उपाय किए जाते हैं। इस संबंध में किए गए कुछ उपायों का उल्लेख संसद में 23 फरवरी, 1994 को प्रस्तुत किए जाने वाले लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-I की पृष्ठ संख्या 1 एवं 150 पर किया गया है।

(ग) से (ङ) वित्तीय हानि की सीमाओं, उद्यमों में सुधारों के जरिए की जाने वाली बचत के लक्ष्य तथा किए जाने वाले सुधारों में लगने वाली राशि के संबंध में कोई अनुमान कर पाना संभव नहीं है क्योंकि ये वर्ष-दर-वर्ष तथा उद्यम-दर-उद्यम भिन्न-भिन्न होंगे। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल 45 रुग्ण उद्यमों के नवीकरण/पुनर्स्थापन की योजनाएं बनाने हेतु उन्हें पंजीकृत कर चुका है। सुधार संबंधी उपाय तथा उनपर किया जाने वाला व्यय भी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल द्वारा नवीकरण/पुनर्स्थापन के संबंध में अनुशंसित योजनाओं पर निर्भर करेगा।